



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91]
No. 91]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1987/फाल्गुन 8, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1987/PHALGUNA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1987

आदेश

का. प्रा. 144(अ)/18चक/18कक/आई.डी.प्रार. ए./
86.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. प्रा. 613(अ)/
18चक/18कक/आई.डी. प्रार. ए/76, दिनांक 15 सितम्बर,
1976 द्वारा इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ
इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता जिसे अब भारतीय औद्योगिक
पुनर्निर्माण बैंक कहा जाता है को (जिसे इसमें इसके पश्चात्
प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड,
कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45-टंगरा रोड, कलकत्ता और 3,
पगलाडांगा रोड, कलकत्ता स्थित औद्योगिक उपक्रमों के
सम्पूर्ण प्रबन्धों को 15 सितम्बर, 1976 से पांच वर्ष की
अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विकास विभाग) के आदेशों द्वारा उक्त आदेश की अवधि
समय-समय पर 28 फरवरी, 1986 तक जिसके अन्तर्गत
यह तारीख भी सम्मिलित है की अवधि के लिए बढ़ा
दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि सर्वसाधारण
के हित में यह समीचीन था कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक
उपक्रमों का प्रबन्ध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा
18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन
कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिया था जिसमें यह प्रार्थना की
गई कि ऐसा प्रबन्ध तारीख 30 जून, 1987 तक जिसके
अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिये
जारी रखा जाये।

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 25 फरवरी, 1987 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दोनों औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध तारीख 30 जून, 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की ओर अवधि तक जारी रखने के लिये अनुज्ञात कर दिया था।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18क के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) के परम्पुक्त द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति को निर्देश देती है कि वह 30 जून, 1987 तथा जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की ओर अवधि के लिये उक्त दोनों औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध करना जारी रखे।

[फा. सं. 2(19)/75-सी. यू. एस.]

ए. वी. गोकक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th February, 1987

ORDER

S.O. 144(E)|18FA|18AA|IDRA|86.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976, the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, now known as Industrial Reconstruction Bank of India (hereinafter referred

to as the authorised person), to take over the management of the whole of the two Industrial Undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta, and at 3, Pagladanga Road, Calcutta, owned by Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976.

And, whereas, the duration of the said order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive of the 28th February, 1987.

And, whereas the Central Government being of opinion that it was expedient in the interest of the general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertakings made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto and inclusive of 30th June, 1987;

And whereas, the said High Court by its Order dated the 25th February, 1987 permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of 30th June, 1987.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1987.

[F. No. 2(19)|75-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1987/फाल्गुन 8, 1908
No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1987/PHALGUNA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1987

अधिसूचना

इलायची नियंत्रण

का. आ. 145(अ):—केन्द्रीय सरकार, मसाला उपकर अधिनियम, 1986
की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के प्रयोजनार्थ उपकर के बतौर 26 फरवरी,